



2026:RJ-JP:8546



[2026:RJ-JP:8546]

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 2660/2009

National Insurance Company Limited, Local Branch
Jatiya Bazar, Sikar, Rajasthan.

----Appellant/Non-Claimant

Versus

1) Manphool Ram son of Shri Jetaram, resident of
Village Deenva, District Jhunjhunu, at present Ward
No. 42, Charan Singh Nagar, Sikar, Tehsil and District
Sikar (Raj.)

2) Smt. Bhagoti Devi wife of late Shri Deshbhakt,
resident of Thimoli, Tehsil Fatehpura, District Sikar, at
present Ward No. 42, Chaudhary Charan Singh Nagar,
Sikar (Raj.)

----Respondents-Non-Claimant

For Appellant(s) : Mr. Rajeev Bhushan Bansal,
Adv.

For :
Respondent(s)

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

24/02/2026

अपीलार्थी—विपक्षी संख्या.—2/बीमा कंपनी (जिसे आगे
विपक्षी संख्या—2 कहा जाएगा) की ओर से यह अपील विद्वान
न्यायालय आयुक्त कर्मकार क्षतिपूर्ति, **सीकर** द्वारा प्रकरण
N.F./28/2007 में पारित निर्णय दिनांक **14.11.2008** से व्यथित
होकर पेश की है, जिसके माध्यम से प्रत्यर्थी/दावेदार के पक्ष में



कुल **3,87,187/-**रूपये प्रतिकर 09 प्रतिशत ब्याज सहित दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया।

यद्यपि यह अपील लंबे समय से प्रत्यर्थागण पर नोटिस तामील होने हेतु लंबित है, लेकिन इसी प्रक्रम पर अपील की पोषणीयता के बिन्दु पर अपीलार्थी – विपक्षी संख्या-2 की बहस सुनी गयी, अभिलेख का अवलोकन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी-बीमा कंपनी का निवेदन है कि इस प्रकरण में चिकित्सक द्वारा जो स्थायी निशक्तता निर्धारित की गयी थी उससे अधिक स्थायी निशक्तता मानकर प्रतिकर राशि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिलायी गयी है तथा ब्याज भी अत्यधिक व अनुचित है। प्रतिकर राशि यथोचित रूप से घटाये जाने का निवेदन किया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक निर्णय North East Karnataka Road Transport Corporation Vs. Smt. Sujatha (2019) 11 SCC 514) के पैरा संख्या-9, 10, 11 तथा 12 सुसंगत है, जो निम्नानुसार है—

9. At the outset, we may take note of the fact, being a settled principle, that the question as to whether the employee met with an accident, whether the accident occurred during the course of employment, whether it arose out of an employment, how and in what manner the accident occurred, who was negligent in causing the accident, whether there existed any relationship of employee and employer, what was the age and monthly salary of the employee, how many are the dependents of the deceased employee, the extent of disability caused to the employee due to injuries suffered in an accident, whether there was any



insurance coverage obtained by the employer to cover the incident etc. are some of the material issues which arise for the just decision of the Commissioner in a claim petition when an employee suffers any bodily injury or dies during the course of his employment and he/his LRs sue/s his employer to claim compensation under the Act.

10. The afore-mentioned questions are essentially the questions of fact and, therefore, they are required to be proved with the aid of evidence. Once they are proved either way, the findings recorded thereon are regarded as the findings of fact.

11. The appeal provided under Section 30 of the Act to the High Court against the order of the Commissioner lie only against the specific orders set out in clause (a) to (e) of Section 30 of the Act with a further rider contained in first proviso to the Section that the appeal must involve substantial question of law.

12. In other words, the appeal provided under Section 30 of the Act to the High Court against the order of the Commissioner is not like a Regular First Appeal akin to Section 96 of the Code of Civil Procedure, 1908 which can be heard both on facts and law. The appellate jurisdiction of the High Court to decide the appeal is confined only to examine the substantial questions of law arising in the case.

उपरोक्त न्यायिक निर्णय तथा अधिनियम-1923 की धारा 30 के प्रावधानों के अनुसार आय का प्रश्न तथ्यों से संबंधित है। उपरोक्त निर्णय में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार प्रतिकर की मात्रा, स्थायी निशक्तता, आय की गणना आदि सभी प्रश्न तथ्यों के संबंध में हैं। वर्तमान मामले में दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरांत विचारण



2026:RJ-JP:8546



[2026:RJ-JP:8546]

(4 of 4)

[CMA-2660/2009]

न्यायालय द्वारा आय की गणना की गयी है। उपलब्ध साक्ष्य व सामग्री को नजर-अन्दाज किया गया हो अथवा जो तथ्य अभिलेख पर नहीं हो, उन पर विचार किया गया हो, ऐसी स्थिति नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष दिया गया है, वह पूर्णतः विधिसम्मत है।

चूंकि विधि का कोई सारवान प्रश्न इस मामले में अन्तर्वलित नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में अधिनियम-1923 की धारा-30 के प्रावधानों के अनुसार यह अपील पोषणीय नहीं है, अतः यह अपील खारिज होने योग्य है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलाधीन निर्णय दिनांक **14.11.2008** की पुष्टि करते हुए यह अपील खारिज की जाती हैं।

अभिलेख इस आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय को प्रेषित किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J